पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून शुक्रवार 10 अप्रैल 2020 पेज 8

गणेश चौक पर राशन की दुकान के बाहर लगी लोगों की लंबी लाइन।

संक्षिप्त समाचार

लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र की जनता हुई जागरूक

संवाददाता देहरादून। विश्व सहित देश व प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी जागरूक हो चुकी है। उन्होंने अपने–अपने गांवों में बैरियर लगार बाहर से आने वाले लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसी कड़ी में मसंदावाला के ग्रामीण आगे आए हैं। यहां भारतीय वन अनुसंधान से सटे व कौलागढ़ के पास मसंदावाला गांव के निवासियों द्वारा गाँव में बाहरी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। गांव मसंनदावाला के निवासियों ने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैरियर लगाकर साफ संदेश दिया है कि इस गांव में बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आयेगा।

लॉकडाउन में स्कूल फीस मांगने पर आयोग सख्त

संवाददाता देहरादून। माउंट लिट्रा जी स्कूल के अभिवावकों द्वारा बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी को फोन पर शिकायत की गयी की स्कूल प्रबंधन फोन व मैसेज कर अभिवावकों से स्कूल फीस देने का दवाव बना रहे हैं इसको अध्यक्ष महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया और लॉकडाउन के समय फीस मांगने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आशा रानी को स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। यहां इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने इसके साथ अन्य शिकायत में सेंट जूड्स सकूल देहरादून और आनंद माई स्कूलों से इसी प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि हालत सामान्य होने तक कोई भी स्कूल फीस मांगता है तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है।

ऑटो संचालकों की मदद को सरकार से लगाई गुहार

संवाददाता देहरादून। ऑटो रिक्शा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा है कि देहरादून शहर में लगभग 2392 ऑटो रिक्शा का संचालन होता है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी ऑटो रिक्शा घर पर खड़ी हैं ऐसे ऑटो संचालक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि शहर के सभी ऑटो रिक्शा चालक प्रति दिन आम दिनों में 500 से 600 रुपए कमा लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। इस अवसर पर अरोड़ा ने बताया कि इस महामारी को रोकने के लिए ऑटो रिक्शा चालक लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उसको देखते हुए उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। यदि सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाये तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो सकती है।

नगर निगम द्वारा 51 लाख रुपए का चेक सीएम राहत कोष में दिया जाना मात्र दिखावा

संवाददाता देहरादून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने अपना बयान जारी कर मेयर द्वारा नगर निगम की ओर से 51 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने को दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा यदि नगर निगम फंड में इतनी अधिक मात्रा में रुपये है तो कुछ दिन पूर्व नगर निगम द्वारा आपदा राहत कोष से पहले तो तीन करोड रुपए की मांग क्यों की गई परंतु जब तीन करोड रुपए की मांग पर जिला प्रशासन ने सवाल उठाए तो नगर निगम द्वारा एक करोड रूपया मांग लिया गया उन्होंने दोनों बातों को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे नगर निगम की क्या मंशा है कहा नहीं जा सकता है।

इस पर जिला प्रशासन भी सवाल उठा चुका है दूसरी ओर नगर निगम द्वारा मांगे गए एक करोड़ रुपए से सभी वार्डों, सड़कों ,सरकारी और निजी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का जिक्र किया गया था परंतु नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य आज तक भी पूरा नहीं हुआ और नगर निगम द्वारा बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस कार्य को किया गया उन्होंने नगर निगम को फंड के खर्च किए जाने को लेकर सभी पार्षदों के साथ आम जनता के सामने पारदर्शिता से रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि शहर में लॉकडाउन के चलते हुए व्यापक स्तर पर छिडकाव व सेनिटाइजर व मॉस्क उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है लेकिन अभी तक इस दिशा में नगर निगम ठोस पहल नहीं कर पा रहा है।

जल्द पदोन्नति प्रक्रिया को बहाल करने की मांग

पेंच

संवाददाता

देहरादून। सरकार की हरी झंडी के बाद भी पदोन्नति बहाली में कोरोना का पेंच फंस गया है। लिहाजा मार्च में तमाम विभागों के अधिकारी–कर्मचारी पदोन्नति का लाभ पाए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए।

उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने इस पर चिंता जताते हुए बुधवार को मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जल्द पदोन्नति प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है, जिससे अप्रैल में कोई अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ पाए सेवानिवृत्त न हो।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबे आंदोलन के बाद जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली की लड़ाई जीती। कर्मचारियों के आंदोलन के बीच ही जब कोरोना महामारी का संकट मंडराया तो सरकार ने बीते 18 मार्च को बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली का शासनादेश जारी कर दिया।

उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन को लगा कि मार्च में कोई भी अधिकारी–कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ पाए सेवानिवृत्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के आला अधिकारियों से लेकर समूचे तंत्र के कोरोना से जंग में जुट जाने के कारण विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया बहाल ही नहीं हो सकी। लिहाजा मार्च में कई अधिकारी–कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हो गए। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जिस तरह से अन्य विभागीय काम हो रहे हैं, उसी तरह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी कराई जा सकती है। हमारी मांग है कि इसे जल्द अमल में लाया जाए, ताकि अप्रैल को कोई भी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त न हो।

उत्तराखंड में पदोन्नति प्रक्रिया बहाली में कोरोना का पेंच फंसा

वित्त सचिव से की माह मार्च का वेतन भुगतान करने की मांग

सचिवालय संघ देगा एक दिन का वेतन

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने पर सहमति दी है। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि एक दिन के वेतन कटौती का आदेश जल्द जारी किया जाए।

आउटसोर्स कार्मिकों जल्द मिले मानदेय

उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने विभागों के आउटसोर्स, संविदा और उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को मार्च माह का वेतन जल्द देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि अल्प मानदेय वाले इन कार्मिकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है।

सभी को मिले बीमा कवर

उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों के निकट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता और बीमा कवर देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा।

राशन कार्ड में तुरंत जुड़ेगा नए सदस्य का नाम

राहत

■ मिलेगा नए सदस्यों का राशन

देहरादून। **संवाददाता**

जिन परिवारों के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ने से रह गया है। उनके लिए अच्छी खबर है। ये कार्डधारक अपने क्षेत्र की राशन की दुकान में जाकर परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कार्ड पर उस सदस्य के हिस्से का राशन भी मिलने लगेगा। जिला आपूर्ति विभाग ने यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की है ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी परिवार के समक्ष राशन का संकट उत्पन्न न हो।

नियमानुसार किसी भी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़े जाने के तीन माह बाद उसके हिस्से का राशन मिलना शुरू होता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कई राशन कार्डधारक हैं, जिनके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम कार्ड में जुड़ने से रह गया है या फिर उनका आधार लिंक नहीं हुआ है। जिससे इन परिवारों को जरूरत के मुताबिक राशन नहीं मिल पा रहा। इस मुश्किल वक्त में इन परिवारों के सामने भोजन की किल्लत न आए, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग ने नई पहल की है। जिसके तहत इन परिवारों के राशन कार्ड में प्राथमिकता से छूटे सदस्यों का नाम जोड़ने के साथ उन्हें ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। इसके लिए डीएसओ ने विभाग के अधिकारियों और डाटा ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं।

ऐसे जुड़वाएं नए सदस्य का नाम

जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए उपभोक्ता को राशन कार्ड की फोटो कॉपी, नए सदस्य का फोटो और आधार कार्ड, आय संबंधित प्रमाण पत्र, बैंक खाते की डिटेल राशन डीलर के पास जमा करनी होगी। डीलर से पूर्ति निरीक्षक या दूसरे विभागीय अधिकारी दस्तावेज ले लेंगे। जिन्हें 10 दिन के भीतर प्राथमिकता से ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद उक्त परिवार नए सदस्य के हिस्से का भी राशन ले पाएंगे।

राशन वितरण में भिन्नता बरकरार:

सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन वितरण को लेकर अब भी भिन्नता बरकरार है। कहीं एक महीने का राशन ही वितरित हो रहा है तो कुछ दुकानों में तीन महीने का। इससे उपभोक्ता भी असमंजस में हैं।

विस कार्मिकों से एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देने की अपील

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को विधानसभा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि कोरोना वायरस कोविड 10 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सहयोग करने हेतु तथा कोरोना महामारी से निपटने एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कम से कम एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर अपना बहुमूल्य योगदान जरूर करें, जिससे हम कोरोना की लड़ाई को लड़ने में हर प्रकार से सक्षम हो सकें। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा के कार्मिकों द्वारा समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के दौरान भी उनके अनुरोध पर अपना आर्थिक सहयोग जरूर दिया गया है। अग्रवाल ने आशा व्यक्त की है कि विधानसभा के सभी कर्मीक संकट की इस घड़ी में अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए इस बार भी अपना आर्थिक सहयोग सरकार को जरूर प्रदान करेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।